चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800–345–1111

रजि.न.34300/80 | संख्या 213 | श्री विजय पुरम, रविवार, 09 अगस्त 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन का श्री विजय पुरम आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया

राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा किया एवं स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की

वीर सावरकर को एक निडर क्रांतिकारी बताया, जिनकी देशभक्ति ने पीढ़ियों को प्रेरित किया

आईएनएस उत्क्रोश पहुंचने पर माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया गया

माननीय उपराष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया

राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल स्थित शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करते माननीय उपराष्ट्रपति

वीर सावरकर की कोठरी में श्रद्धांजलि अर्पित करते माननीय उपराष्ट्रपति

राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल स्थित संग्रहालय एवं प्रदर्शनी दीर्घा का दौरा करते माननीय उपराष्ट्रपति

राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल में आगंतुक पुस्तिका में अपनी टिप्पणी अंकित करते माननीय उपराष्ट्रपति

राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम देखते माननीय उपराष्ट्रपति

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त (पीआईबी)

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का दौरा किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपार कष्ट सहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की, वीर सावरकर प्रकोष्ठ में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी तथा स्वतंत्र ज्योति, केंद्रीय मीनार, फांसीघर और संग्रहालय एवं प्रदर्शनी दीर्घा का दौरा किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की वीरगाथा को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को भी देखा।

दौरे के दौरान बोलते हुए, माननीय उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर को एक अद्वितीय और निडर क्रांतिकारी बताया, जिनकी प्रखर देशभक्ति ने भारतीय युवाओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल में सावरकर के कारावास के वर्षों और उनके साथ किए गए कठोर व्यवहार को याद करते हुए उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजने का उद्देश्य उनका मनोबल तोड़ना था, सावरकर जी का मनोबल कभी नहीं टूटा। अंततः ब्रिटिश राज का मनोबल टूट गया।" उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में सावरकर के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने जोर देकर कहा कि भारत का अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास दूसरों पर अपनी शर्तें थोपने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि "हम इस दुनिया में किसी के द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहते, यही वास्तविक स्वतंत्रता है।"

इससे पहले आज, श्री विजय पुरम स्थित आईएनएस उत्क्रोश पहुंचने पर श्री सी. पी. राधाकृष्णन का अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने अण्डमान निकोबार कमान के कमांडर–इन–चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की मुख्य सचिव श्रीमती चंचल यादव, पुलिस महानिदेशक श्री रविंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष, ज़िला परिषद दक्षिण अण्डमान, श्री पी. उमर, अध्यक्ष, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद, श्रीमती वसंता तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दौरान वे 'हर घर तिरंगा' के शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा करेंगे।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन आज 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' में भाग लेंगे

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन, जो वर्तमान में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दो दिवसीय दौरे पर हैं, 9 अगस्त, 2026 को सुबह 10 बजे डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह 'वंदे मातरम् पर तिरंगा कॉन्सर्ट' में भाग लेंगे।

कला एवं संस्कृति निदेशालय से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, माननीय उपराष्ट्रपति सभागार परिसर में लगाई गई 'हर घर तिरंगा प्रदर्शनी' का भी अवलोकन करेंगे। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।

CMYK

"ऑपरेशन ब्लू शील्ड"

मध्योत्तर अण्डमान पुलिस ने नौ म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा, 300 किलोग्राम समुद्री ककड़ी बरामद

मायाबंदर, 8 अगस्त।

एक स्थानीय मछुआरे से संदिग्ध विदेशी घुसपैठिए की डिंगी के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने भारतीय तटरक्षक बल के समन्वय से डिगलीपुर के तटीय क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 28 जुलाई, 2026 को "ऑपरेशन ब्लू शील्ड" शुरू किया।

इसके बाद स्मिथ द्वीप के पीछे हिरन टेकरी के निकट एक संदिग्ध डिंगी के देखे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया। डिंगी को स्मिथ द्वीप के निकट लावारिस अवस्था में पाया गया। उसमें लगभग 300 किलोग्राम समुद्री ककड़ी (सी कुकुम्बर) तथा जीवन रक्षक उपकरण रखे हुए थे, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ज़ब्त कर लिया गया।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विदेशी घुसपैठिए गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में पास के घने जंगल में भाग गए। इसके बाद पुलिस थाना डिगलीपुर, कालीघाट एवं मायाबंदर की अवैध घुसपैठ रोध ी टीमों ने लगातार अभियान चलाते हुए सघन गश्त, व्यवस्थित क्षेत्र की तलाशी तथा खुफिया जानकारी के आधार पर खोज अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण भू–भाग के बावजूद टीमों ने लगातार दबाव बनाए रखा तथा घुसपैठियों को पकड़ने के लिए निरंतर निगरानी एवं समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की। श्री राहुल विक्रम, दानिप्स, प्रभागीय पुलिस अधिकारी, डिगलीपुर के निकट पर्यवेक्षण तथा श्री विकास स्वामी, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक (ज़िला), उत्तर व मध्य अण्डमान के समग्र पर्यवेक्षण में टीमों ने 29 जुलाई, 2026 से 4 अगस्त, 2026 के बीच 5 म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा। स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं तथा तेज किए गए तलाशी अभियानों के आधार पर 8 अगस्त, 2026 को गणेश नगर, वार्ड संख्या–1 से 4 और म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा गया, जिससे पकड़े गए व्यक्तियों की कुल संख्या 9 हो गई। विज्ञप्ति में आमजन से अनुरोध किया गया है कि वे अपराध अथवा अवैध गतिविधियों से संबंधित विश्वसनीय जानकारी निकटतम पुलिस थाने को अथवा हेल्पलाइन नंबर 100, 112 या 03192–273344 पर साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारियों के लिए सर्पदंश विषाक्तता की रोकथाम एवं नियंत्रण पर आभासी प्रशिक्षण सत्र संचालित

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त।

सर्पदंश के मामलों के प्रबंधन में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की चिकित्सीय तैयारी को बढ़ाने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 6 अगस्त, 2026 को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में सर्पदंश विषाक्तता की रोकथाम एवं नियंत्रण पर आभासी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) तथा ज़िला अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेद) ने भाग लिया। यह आभासी प्रशिक्षण डॉ. सुब्रत साहा, राज्य नोडल अधिकारी (पीसीएसबीई) के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

सत्र का संचालन संसाधन व्यक्ति डॉ. शिव शंकर सिंह, एम.डी. (मेडिसिन) द्वारा किया गया, जिन्होंने सर्पदंश के नैदानिक प्रबंधन एवं उपचार के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के ज्ञान एवं तैयारी को बढ़ाना था, ताकि सर्पदंश के मामलों का प्रभावी प्रबंधन, उचित रेफरल व्यवस्था, सर्प विषरोधी (एएसवी) प्रदान करने तथा सर्प विषाक्तता से संबंधित उपचार प्रभावी ढंग से किया जा सके, जिसे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।

यह पहल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण तथा ज़मीनी स्तर पर प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रतिभागियों का स्वागत डॉ. सुब्रत साहा, राज्य नोडल अधिकारी (पीसीएसबीई) द्वारा किया गया। इस आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम से लगभग 100 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. सुब्रत साहा, राज्य नोडल अधिकारी (पीसीएसबीई) तथा डॉ. राजीव घोष, एमपीएच, ज़िला जन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने सभी स्तरों पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रति निदेशालय की प्रतिबद्धता दोहराई।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का समापन सर्पदंश के मामलों से निपटने में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना की तथा अपने–अपने स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में रोगियों के बेहतर उपचार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को लागू करने का संकल्प लिया।

मायाबंदर में सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित

मायाबंदर, 8 अगस्त

पीएम श्री योजना के अंतर्गत 7 अगस्त, 2026 को पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान में पहचान एवं मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 08 विद्यार्थियों (05 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और 03 संदिग्ध मामले) तथा उनके माता–पिता ने भाग लिया। चिकित्सा दल में डॉ. मुस्कान अकबर (चिकित्सा अधिकारी), डॉ. थिरुमणि पृथ्वी (बाल रोग विशेषज्ञ), डॉ. शालिनी जीवन (दंत चिकित्सा–जीडीएमओ) और श्रीमती गीता बिस्वास (स्वास्थ्य शिक्षिका) शामिल थीं, जिन्होंने आवश्यक मूल्यांकन किए। शिविर का समन्वय श्री प्रकाश राव (पीजीटी) द्वारा किया गया, जिसमें श्रीमती अथिका (जीटीटी) आंतरिक पर्यवेक्षक तथा श्री आकाश सिंह (बीआरपी–विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) के रूप में उपस्थित रहे। यह शिविर श्री प्रकाश हाउलादार, खंड परियोजना अधिकारी, मायाबंदर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार शिविर का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, मूल्यांकन तथा उनके लिए उचित सहायता प्रदान करना था।

माइलतिलक एवं गुप्तापाड़ा में "नशामुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान" पर चेतना लाई गई

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त

नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत, अण्डमान तथानिकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय ने माइल तिलक गांव और फिश लैंडिंग सेंटर, गुप्तापाड़ा में "नशामुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान" विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

एकीकृत नशामुक्ति केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला तथा केंद्र में उपलब्ध नशामुक्ति एवं पुनर्वास सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा की। नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना के परियोजना समन्वयक ने नशीले पदार्थों एवं शराब के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला तथा जनता, विशेषकर माता–पिता एवं युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। प्रतिभागियों को एकीकृत नशामुक्ति केंद्र में उपलब्ध परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न विभागों के संसाधन व्यक्तियों ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। कार्यक्रमों का समापन प्रतिभागियों द्वारा "नशीले पदार्थों को ना, जीवन को हां" की शपथ लेने के साथ हुआ। संवादात्मक सत्र के दौरान संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया गया।

अनिम्स में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश

प्रॉस्पेक्टस–सह–आवेदन पत्र उपलब्ध

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स), श्री विजय पुरम को शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा एमबीबीएस की 114 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। नीट–2026 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अखिल भारतीय कोटा काउंसलिंग तथा राज्य कोटा काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। स्वीकृत 114 सीटों में से 17 सीटें अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत मेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी) द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी, जबकि शेष 97 सीटों पर राज्य कोटा (10 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तथा 87 श्रेणीवार सीटें) के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा।

'अनिम्स' में प्रवेश के लिए नीट पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अभ्यर्थी कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल **https://collegeadmission.andamannicobar.gov.in** तथा संस्थान की वेबसाइट **www.aniims.andamannicobar.gov.in** के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 17 अगस्त, 2026 को सुबह 11 बजे महाविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य कोटा की उपर्युक्त 97 सीटों के लिए केवल अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नीट–2026 उत्तीर्ण विद्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। शेष 17 अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश मेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी) द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

कार्यक्रम	तिथि एवं समय
विधिवत भरे हुए आवेदन–पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ	8 अगस्त, 2026
आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	16 अगस्त, 2026
अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	17 अगस्त, 2026, सुबह 11 बजे
अपील एवं शिकायत	17 अगस्त, 2026, दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त, 2026, शाम 3 बजे तक
अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	19 अगस्त, 2026, शाम 5 बजे
प्रथम चरण की काउंसलिंग एवं दस्तावेज़ों का सत्यापन	21 एवं 22 अगस्त, 2026
प्रवेश ग्रहण करने की अंतिम तिथि	28 अगस्त, 2026
द्वितीय चरण की काउंसलिंग एवं दस्तावेज़ों का सत्यापन	8 सितंबर, 2026
प्रवेश ग्रहण करने की अंतिम तिथि	14 सितंबर, 2026
तृतीय चरण की काउंसलिंग एवं दस्तावेज़ों का सत्यापन	26 सितंबर, 2026
प्रवेश ग्रहण करने की अंतिम तिथि	1 अक्टूबर, 2026
रिक्त बची सीटों हेतु काउंसलिंग (यदि आवश्यक हो)	5 अक्टूबर, 2026
प्रवेश ग्रहण करने की अंतिम तिथि	10 अक्टूबर, 2026
एमबीबीएस शैक्षणिक सत्र 2026–27 का शुभारंभ	8 सितंबर, 2026

नोटः काउंसलिंग की तिथियां अस्थायी हैं तथा मेडिकल काउंसलिंग समिति (एमसीसी) के समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को अद्यतन जानकारी के लिए **https://aniims.andamannicobar.gov.in** तथा संस्थान के सूचना पट्ट का नियमित रूप से अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा प्रश्न के लिए अभ्यर्थी 'अनिम्स' प्रवेश प्रकोष्ठ से दूरभाष संख्या 03192–230258 पर संपर्क कर सकते हैं।

'डीब्राइट' में अतिथि संकाय, अंशकालिक प्रशिक्षकों एवं योग प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार 13 अगस्त को

श्री विजय पुरम, 8 अगस्त

शैक्षणिक सत्र 2026–27 (विषम सेमेस्टर) के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिष्ठान में विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिथि संकाय (जीएल), अंशकालिक प्रशिक्षकों (पीटीआई) एवं योग प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए 13 अगस्त, 2026 को प्रत्यक्ष साक्षात्कार (प्रदर्शन, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) निर्धारित किया गया है।

योग्यताओं, साक्षात्कार की समय–सारणी एवं प्रदर्शन विषयों का विवरण संस्थान की वेबसाइट **https://dbrait.andamannicobar.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की एक प्रति के साथ अपना जीवन–वृत्त लाने के लिए सूचित किया गया है। प्राप्त विज्ञप्ति में उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए मूल प्रमाण–पत्र भी साथ लाने के लिए सूचित किया गया है। किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक संस्थान के शैक्षणिक प्रकोष्ठ से दूरभाष संख्या 03192–259818 पर संपर्क कर सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

छठी पीढ़ी के 'फाइटर जेट प्रोजेक्ट' में फ्रांस के साथ शामिल होगा भारत

नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.)। पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिए जूझ रहे भारत ने फ्रांस के साथ छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम में शामिल होने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसका मकसद घरेलू पांचवीं पीढ़ी के एएमसीए प्रोजेक्ट के साथ–साथ भविष्य के हवाई युद्ध के गैप को भरना है। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (एफसीएएस) को फ्रांस सरकार लीड कर रही है। पार्लियामेंट्री पैनल ने रक्षा मंत्रालय से ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने का रोडमैप मांगा है।

रक्षा मंत्रालय ने छठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के मुद्दे पर डिफेंस पर स्टैंडिंग कमिटी को बताया है कि भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी छठी जेनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए ठोस कोशिशें शुरू की हैं। फ्रांस की अगुवाई में इस कार्यक्रम का मकसद अगली पीढ़ी के फाइटर जेट को युद्ध के आसमान में उतारना है, जो कॉम्बैट क्लाउड के जरिए रिमोट कैरियर स्वार्मिंग ड्रोन से जुड़ा हो। यह एक बराबर साझेदारी वाला कार्यक्रम है, जिसका मकसद ऑपरेशनल तैयारी को टारगेट करना है।

हालांकि, भारत अपने स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) को अलग से बना रहा है, इसलिए भारत ने फ्रांस के नेतृत्व वाले एफसीएएस फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करने और उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए औपचारिक रूप से यह कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में भागीदारी का मकसद छठी पीढ़ी के जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि मैन्ड–अनमैन्ड टीमिंग (लॉयल विंगमैन ड्रोन), एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉम्बैट क्लाउड नेटवर्किंग और हाई–थ्रस्ट प्रोपल्शन तक जल्दी पहुंच बनाना है।

संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में रक्षा पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भविष्य के वायु केंद्रित युद्ध में भारत की एयर डोमेन क्षमताएं बढ़ाने के लिए छठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। कमेटी को बताया गया है कि छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए यूके, इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (एफसीएएस) को फ्रांस सरकार लीड कर रही है। इसलिए भारतीय वायु सेना इस एफसीएएस कार्यक्रम में शामिल होगी, ताकि भारत पिछड़ने के बजाय एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के विकास में दुनिया के साथ रहे।

उपभोक्ता निश्चिंत होकर ई20 पेट्रोल का कर सकते हैं उपयोग, निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है ईंधन– सरकार

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर सामने आई चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को इस ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह भरोसे के साथ जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा ई20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और इसकी निगरानी के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था लागू है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में ई20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद तेल कंपनियों ने पूरे देश में ई20 पेट्रोल की सप्लाई चेन में अतिरिक्त और व्यापक परीक्षण अभियान चलाया।

सरकार के अनुसार, इन परीक्षणों के नतीजों से यह साफ हुआ है कि ईंधन की गुणवत्ता निर्धारित सीमा से काफी बेहतर स्तर पर बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों से किए गए व्यापक और यादृच्छिक परीक्षणों में ईंधन के दूषित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

बयान में कहा गया, ष्कुछ दावों के विपरीत, वैज्ञानिक आधार पर किए गए व्यापक परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ है कि ईंधन में किसी प्रकार के प्रदूषण या गुणवत्ता संबंधी समस्या को लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है। तेल कंपनियों ने भी ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि ईंधन की गुणवत्ता उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कभी कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिससे वाहन के प्रदर्शन या उपभोक्ता विश्वास पर असर पड़ सकता हो, तो उसकी तत्काल वैज्ञानिक जांच की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, ईंधन की गुणवत्ता पर निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए देश भर के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर रोजाना 8 से 12 बार पानी की मिलावट और घनत्व की जांच की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स भी तैनात की गई हैं। इन परीक्षणों के परिणामों की स्वतंत्र ईंधन प्रयोगशालाओं से पुष्टि कराई जाती है, ताकि गुणवत्ता आश्वासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जा सके।

सरकार ने कहा कि सप्लाई चेन के हर स्तर पर लागू इन बहुस्तरीय और सख्त परीक्षण प्रणालियों ने एक बार फिर भारत के ईंधन गुणवत्ता मानकों की मजबूती को साबित किया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश की विभिन्न रिफाइनरियों से 100 से अधिक अतिरिक्त पेट्रोल नमूने यादृच्छिक रूप से लेकर उनकी जांच की गई। परीक्षण में सभी नमूनों में क्लोराइड का स्तर 1 पार्ट पर मिलियन (पीपीएम) या उससे कम पाया गया, जो निर्धारित मानकों के भीतर है।

मंत्रालय ने दोहराया कि ई20 पेट्रोल देश की ऊर्जा सुरक्षा, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे में उपभोक्ता बिना किसी चिंता के ई20 पेट्रोल का उपयोग जारी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है।–आईएएनएस

15 अगस्त सिर्फ भारत का नहीं... इसी दिन 5 और देशों में भी मनता है आजादी का जश्न

नई दिल्ली, 08 अगस्त। 15 अगस्त का नाम आते ही भारत की आजादी का इतिहास, तिरंगा और देशभक्ति का माहौल आंखों के सामने आ जाता है. हर साल इस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों के लिए भी ऐतिहासिक महत्व रखता है. यही वजह है कि यह तारीख वैश्विक स्तर पर भी विशेष मानी जाती है.

दुनिया के पांच अन्य देश भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. इन देशों की आजादी अलग–अलग समय और अलग–अलग परिस्थितियों में मिली, लेकिन राष्ट्रीय उत्सव की तारीख एक ही है. आइए जानते हैं कि भारत के अलावा किन देशों के लिए 15 अगस्त राष्ट्रीय गौरव का दिन है और उनकी आजादी का इतिहास क्या कहता है.

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ जापानी शासन समाप्त हुआ और कोरियाई प्रायद्वीप को आजादी मिली. इसी ऐतिहासिक घटना की याद में दोनों देश हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं.

बहरीन भी 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता से जुड़ी ऐतिहासिक तिथि के रूप में याद करता है. वर्ष 1971 में देश ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी. इसके बाद बहरीन ने अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित की. यह दिन वहां के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है.

अफ्रीका का कांगो गणराज्य भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है. वर्ष 1960 में देश को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी. इसके बाद कांगो ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की. हर साल इस अवसर पर वहां विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

यूरोप का छोटा–सा देश लिकटेंस्टीन भी 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है. उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार वर्ष 1866 के बाद इस देश ने स्वतंत्र पहचान स्थापित की. आज यह तारीख वहां राष्ट्रीय एकता और गौरव के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है.

भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी. इसी दिन देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई शुरुआत की. हर वर्ष प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. यही कारण है कि 15 अगस्त भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में गिना जाता है, जबकि इसी दिन कई अन्य देश भी अपनी आजादी का उत्सव मनाते हैं.

सीबीएसई 10वीं के छात्रों का आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली, 08 अगस्त। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट गतिविधियों की शुरुआत कर दी है। बोर्ड ने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। इसके बाद 14 अगस्त 2026 से उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन और री–इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 2026 की मुख्य बोर्ड परीक्षा या मुख्य एवं सेकेंड बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था।

सीबीएसई के अनुसार आवेदन करने के पात्र छात्रो में 2026 की कक्षा 10 मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्र, मुख्य बोर्ड परीक्षा और सेकेंड बोर्ड परीक्षा दोनों में शामिल छात्र और निजी और नियमित दोनों श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

इस वर्ष भी सीबीएसई की संशोधित और पारदर्शी प्रक्रिया लागू रहेगी। इसके तहत छात्रों को पहले अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही वे उत्तरों के वेरिफिकेशन या री–इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रक्रिया का क्रम– उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन। स्कैन कॉपी प्राप्त करना।

यदि आवश्यकता हो तो अंकों/उत्तरों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन। इसके बाद संबंधित उत्तरों के री–इवैल्यूएशन के लिए आवेदन।

सीबीएसई ने बताया है कि स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने

के बाद 14 अगस्त 2026 से वेरिफिकेशन और री–इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

छात्र सीबीएसई के आधिकारिक पोस्ट रिजल्ट पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक पोर्टल खोलें।

स्टेप 2. Post Result Activities सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4. संबंधित विषय चुनें।

स्टेप 5. निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 6. आवेदन सबमिट कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

पहले स्कैन कॉपी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और केवल उन्हीं प्रश्नों के लिए री–इवैल्यूएशन कराएं, जहां मूल्यांकन में त्रुटि दिखाई दे। छात्र आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक हो सकता है। सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

विदेश मंत्रालय से जुड़ी सटीक जानकारी अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'स्नैपचैट' पर मिलेगी

नई दिल्ली, 08 अगस्त। भारत का विदेश मंत्रालय (एमईए) अब एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। लाखों की तादाद में फॉलोअर्स अहम और सटीक जानकारी एक और प्लेटफॉर्म पर हासिल कर पाएंगे। गुरुवार को एमईए ने 'स्नैपचैट' पर कदम रखने का ऐलान किया। मंत्रालय ने यूजर्स से अपने आधिकारिक स्नैपचैट अकाउंट से जुड़ने की अपील की है।

एमईए ने एक वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। फॉलोअर्स से जुड़ने की अपील करते हुए दावा किया कि यहां उन्हें "एक्सक्लूसिव स्टोरीज, अपडेट, रोचक कंटेंट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी।" फेसबुक, वॉट्सऐप, एक्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया/मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए काफी समय से एमईए विभिन्न देशों के मिशन (दूतावास/ उच्चायोग) से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा करता रहा है।

स्नैपचैट एक लोकप्रिय मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप है जो नई पीढ़ी (जेन–जी) के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें भेजे गए फोटो और छोटे वीडियो को स्नैप कहा जाता है जिनकी विशेषता ये है कि देखने के कुछ सेकंड के बाद ये अपने आप गायब हो जाते हैं। वहीं इनमें साझा की गई फोटो और वीडियो 24 घंटे तक यूजर के प्रोफाइल पर दिखती है।

विदेश मंत्रालय पहले भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा है और समय–समय पर लोगों को फर्जी खातों और विदेश नीति से जुड़ी सशुल्क सलाह देने वाले स्कैमर्स से सावधान रहने की चेतावनी जारी करता रहा है। मंत्रालय अकसर अपने कूटनीतिक संवाद, उच्चस्तरीय बैठकों और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को दर्शाने वाले वीडियो और तस्वीरें भी साझा करता रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों की झलक मिलती रहे।

जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में विदेश मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक फैक्ट चेक अकाउंट भी लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी फर्जी खबरों, अफवाहों और भ्रामक दावों का तेजी से खंडन करना है। (इनपुट–आईएएनएस)

इतिहास के पन्नों में 09 अगस्तः करो या मरो के नारे के साथ शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन

नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.)। 09 अगस्त का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। वर्ष 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को स्वतंत्र कराना था। मुंबई के गौवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी ने देशवासियों से करो या मरो का आह्वान किया।

गांधीजी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में अंग्रेजो भारत छोड़ो का नारा देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे हिंसा का मार्ग न अपनाएं और सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजी शासन का विरोध करें। यह आंदोलन देशव्यापी बन गया और लाखों भारतीयों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद, आंदोलन पूरे देश में फैल गया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। भारत छोड़ो आंदोलन से ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई और अंततः यही आंदोलन भारत को 1947 में आजादी दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हुआ। अन्य प्रमुख घटनाएंः–1173 – दुनिया के सात अजूबों में से एक इटली के पीसा की झुकी मीनार का निर्माण शुरू हुआ।

1831 – अमेरिका में पहली बाद स्टीम इंजन ट्रेन चली।

1892–थॉमस अल्वा एडिसन ने टू–वे टेलिग्राफ का पेटेंट कराया।

1910 – अल्वा फिशर ने बिजली से चलने वाली वाशिंग

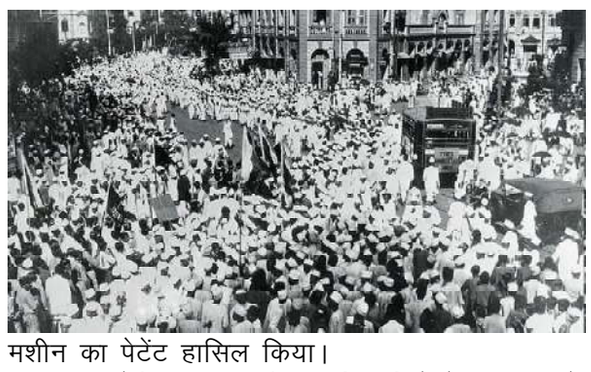

मशीन का पेटेंट हासिल किया।

1925–काकोरी कांडः भारतीय क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन से जा रहे सरकारी खजाने को लूटा।

1942 – महात्मा गांधी ने मुंबई में करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की।

1942–नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने मलाया (अब मलेशिया) में जापान की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की।

1945 – अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया।

1965 – सिंगापुर, मलेशियाई संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना।

1971–भारत और पाकिस्तान ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।

1974 – वॉटरगेट कांड का खुलासा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पद से इस्तीफा दिया।

2012 – भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि–2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

हवाई अड्डों की साइबर सुरक्षा होगी अभेद्य, सीआईएसएफ ने आईआईटी रोपड़ के साथ मिलाया हाथ

नई दिल्ली, 08 अगस्त। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत और अभेद्य बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एयरपोर्ट सेक्टर की ओर से 7 अगस्त को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रोपड़ के साथ एक अहम समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत सीआईएसएफ जवानों को साइबर सुरक्षा में निपुण बनाने के लिए छह सप्ताह की विशेष आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन के नेतृत्व में त्वरित समाधान करने के लिए विशेष जवानों की एक टीम तैयार की जाएगी। हवाई अड्डे देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में से एक हैं। ऐसे में यहां होने वाला कोई भी साइबर व्यवधान बड़े पैमाने पर सुरक्षा, संचालन और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए यह विशेष कैडर तैयार किया जा रहा है।

आईआईटी रोपड़ एससीएएलई फाउंडेशन और सीआईएसएफ की इस संस्थागत साझेदारी के तहत छह सप्ताह का यह कार्यक्रम पूरी तरह से निशुल्क आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग में जवानों को किताबी ज्ञान के साथ–साथ जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों से भी रूबरू कराया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, डिजिटल फोरेंसिक और घटनाओं का पता लगाना, आपदा रिकवरी और व्यापार निरंतरता, नए व उभरते साइबर खतरे, और मल्टी–सेक्टर क्राइसिस सिमुलेशन जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

आईआईटी रोपड़ के साथ यह साझेदारी सीआईएसएफ को तकनीक के मोर्चे पर और भी मजबूत व भविष्य के लिए तैयार करेगी। इस विशेष श्साइबर सुरक्षा कैडरश के तैयार होने से न केवल विमानन सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को भी एक नई ताकत देगा।–आईएएनएस

भारत का मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2047 तक 250 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली, 08 अगस्त (आईएएनएस)। भारत का मेडिकल डिवाइस उद्योग आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार करते हुए वर्ष 2047 तक 250 अरब डॉलर के बाजार तक पहुंच सकता है। यह बात शुक्रवार को फिक्की–डीयूए कंसल्टिंग द्वारा 'भारतीय हेल्थकेयर में मेडिकल इक्विपमेंट की सर्विस और मेंटेनेंस–सुरक्षित, भरोसेमंद और टिकाऊ मेडिकल डिवाइस मेंटेनेंस इकोसिस्टम की ओर' विषय पर जारी रिपोर्ट में कही गई है।

शुक्रवार को फिक्की (एफआईसीसीआई) के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आयोजित 'इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026' के 9वें एडिशन के उद्घाटन सत्र में जारी व्हाइट पेपर में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर के मूल्य वाला भारत का मेडिकल डिवाइस उद्योग इस दशक के अंत तक 30–50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और वर्ष 2047 तक इसका आकार बढ़कर 250 अरब डॉलर होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता, अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को तेजी से अपनाया जाना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां तथा भारत को वैश्विक मेडटेक हब बनाने की महत्वाकांक्षा इस क्षेत्र की तेज वृद्धि के प्रमुख कारण होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और मेडिकल डिवाइस उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना जैसी सरकारी पहलों से घरेलू विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन योजनाओं ने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी मजबूत किया है।

व्हाट्सएप मैलवेयर हमले से 10,000 से अधिक भारतीयों को बचाया गया– गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की समन्वित कार्रवाई के जरिए व्हाट्सऐप अकाउंट हैक करने वाले एक बड़े मैलवेयर अभियान से 10,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से कमांड एंड कंट्रोल (सी2) सर्वरों को जियो–ब्लॉक करने सहित कई कदम उठाए गए, जिससे इस साइबर हमले के प्रभाव को रोका जा सका।

गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर हाल के दिनों में व्हाट्सऐप अकाउंट टेकओवर से जुड़ी शिकायतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। ये हमले ऐसे मैलवेयर के जरिए किए जा रहे हैं, जिन्हें अकाउंट स्टेटमेंट या किसी सरकारी नियामक संस्था के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में छिपाकर भेजा जाता है।

मंत्रालय ने कहा, इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से अब तक 10,000 से अधिक भारतीयों को इस साइबर अभियान से सुरक्षित किया गया है। सहयोग पोर्टल के जरिए मैलवेयर से जुड़े सर्वरों को लगातार ब्लॉक किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में सामने आई हैं। आई4सी ने इससे पहले 22 जून को भी एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे साइबर हमलों के प्रति सतर्क किया था, जिनमें सरकारी या नियामक अधिकारियों का रूप धारण कर व्हाट्सऐप अकाउंट पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है।

मंत्रालय ने बताया कि साइबर अपराधी आमतौर पर व्हाट्सऐप, एसएमएस या ई–मेल के माध्यम से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट-जिप, आरबीआई–जिप या एमसीए–जिप जैसे नामों वाली संपीड़ित (-जिप) फाइलें भेजते हैं। कई मामलों में फाइलों के नाम के आगे तारीख भी लिखी होती है, ताकि वे अधिक विश्वसनीय दिखाई दें।

ये संदेश इस तरह तैयार किए जाते हैं कि वे किसी बैंक खाते के विवरण, वित्तीय दस्तावेज या किसी नियामक संस्था की तत्काल सूचना जैसे प्रतीत हों। इससे लोग बिना सोचे–समझे फाइल खोल लेते हैं।

मंत्रालय ने बताया, जब कोई व्यक्ति अपने विंडोज डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इन जिप (जेडआईपी) फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर खोलता है, तो उसके सिस्टम में एक ट्रोजन मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो डिवाइस को हैक कर लेता है और पीड़ित के सक्रिय व्हाट्सऐप वेब सेशन को हाईजैक कर लेता है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि कई मामलों में साइबर अपराधी आयकर विभाग के नाम से फर्जी ई–मेल भी भेज रहे हैं, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके।

एक बार व्हाट्सऐप अकाउंट हैक होने के बाद अपराधी उस अकाउंट का इस्तेमाल पीड़ित के सभी संपर्कों और ग्रुप्स में वही संक्रमित फाइल भेजने के लिए करते हैं। अक्सर संदेश में लिखा होता है कि फाइल को 'कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को वेरिफिकेशन के लिए भेजें' और कंप्यूटर पर खोलें।

गृह मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान या संदिग्ध जिप फाइल को डाउनलोड या ओपन न करें। यदि कोई संदेश बैंक, आरबीआई, एमसीए, आयकर विभाग या किसी अन्य सरकारी संस्था के नाम से प्राप्त होता है, तो उसकी सत्यता की जांच आधिकारिक माध्यमों से अवश्य करें। साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट साइबर क्राइम डॉट गव डॉट इन (www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।–आईएएनएस

अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता, आयात में हिस्सेदारी बढ़कर 67 प्रतिशत पहुंची–केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

नई दिल्ली, 08 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अमेरिका अब भारत को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। पिछले कुछ महीनों में भारत के एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और अब यह लगभग 67 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति रणनीति पर बात करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने पहले ही अमेरिका से देश की कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 10 प्रतिशत आयात करने का फैसला किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी भू–राजनीतिक संकट या होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान की आशंका के कारण नहीं लिया गया था, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा था।

मंत्री ने बताया कि उस समय इस फैसले को लेकर कई सवाल उठे थे, क्योंकि भारत पहले से ही अपने नजदीकी देशों और क्षेत्रों से एलपीजी आयात करता रहा है। हालांकि समय के साथ भारत के आयात ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला और अमेरिका देश का प्रमुख एलपीजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 67 प्रतिशत हो गई है।

ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में घोषित 84,000 करोड़ रुपए के

समुद्र मंथन मिशन का उल्लेख करते हुए पुरी ने कहा कि यह परियोजना भारत में गहरे समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन खोज गतिविधियों को अभूतपूर्व गति देगी। उन्होंने कहा, समुद्र मंथन मिशन केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य में विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह मिशन देश के ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तनकारी अध्याय लिखेगा और भारत को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

उनके अनुसार, भारत ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, मजबूत ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने, भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बनाने, रणनीतिक भंडार तैयार करने और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए हैं, जिससे बाहरी परिस्थितियों और वैश्विक संकटों का असर आम नागरिकों पर कम करने में मदद मिली है।–आईएएनएस

वैज्ञानिक संस्थान अब सामाजिक जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे– केन्द्रीय मंत्री

लखनऊ, 08 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक संस्थान अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं बल्कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों को उभरती पर्यावरणीय एवं जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समन्वय करना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को यहां इको–एजुकेशनल हब का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–एनबीआरआई), लखनऊ ने बन्थरा स्थित महर्षि पराशर बायोरिसोर्स सेंटर (एमपीबीसी) में विकसित प्रकृति ज्ञानधाम राष्ट्र को समर्पित किया। यह एकीकृत परिसर देश का अपनी तरह का पहला इको–एजुकेशनल हब है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण, संस्कृति और जन–जागरूकता को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह इको–एजुकेशनल हब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस परिकल्पना को साकार करता है, जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जनभागीदारी को एकीकृत करते हुए देश की वानस्पतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। यह केंद्र विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्यावरण शिक्षा, जैव विविधता संरक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम का एक अनूठा मंच सिद्ध होगा। उन्होंने किसानों, उद्योगों तथा आम जनता के

हित में वैज्ञानिक अनुसंधान को उपयोगी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए सीएसआईआर–एनबीआरआई के प्रयासों की सराहना की।

इससे पूर्व स्वागत भाषण देते हुए सीएसआईआर–एनबीआरआई तथा सीएसआईआर–आईआईआईएम, जम्मू के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान द्वारा पादप विज्ञान अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला।

संस्थान ने अपने क्यूआर–कोड आधारित सूचना एवं व्याख्या तंत्र का भी प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से आगंतुक डिजिटल माध्यमों से पौधों से संबंधित वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सतत पर्यटन एवं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति पथ, पर्यावरण–अनुकूल विद्युत वाहन परिवहन तथा प्रस्तावित मियावाकी शहरी वन को भी इस परिसर में शामिल किया गया है।

जेम ने सार्वजनिक खरीद में बदलाव का एक दशक पूरा किया, कुल जीएमवी 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा

नई दिल्ली, 08 अगस्त। सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) 09 अगस्त 2026 को अपने कामकाज का दस वर्ष पूरा कर लेगा। तकनीक, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीदारी में बदलाव के इस दशक में प्लेटफॉर्म ने 3.78 करोड़ से अधिक ऑर्डर प्राप्त कर 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कुल व्यापार मूल्य (जीएमवी) हासिल किया है, जो भारत की सार्वजनिक खरीददारी प्रणाली में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

सालाना जीएमवी वित्त वर्ष 2016–17 में 422 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 और 2025–26 दोनों में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। केवल वित्त वर्ष 2026–27 के शुरुआती चार महीनों में ही जेम ने 1,47,888 करोड़ रुपये का जीएमवी दर्ज किया। कुल जीएमवी में 10 लाख करोड़ का पहला आंकड़ा छूने में आठ वर्षों से ज्यादा समय लगा, लेकिन अगला 10 लाख करोड़ दो वर्षों से भी कम में हासिल हो गयाकृसार्वजनिक खरीद प्रणाली को तेजी से अपनाने और बढ़ती भागीदारी का संकेत।

पिछले दशक में भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। प्रोफाइल पूरा करने वाले विक्रेताओं की संख्या 3,339 से 25.45 लाख हो गई, मुख्य खरीददार संगठन 1,707 से 1.37 लाख, और पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) 2,424 से 12.25 लाख हो गए। एमएसई ने 9.07 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर पूरे किए–कुल जीएमवी का 45.6 प्रतिशत। 2.24 लाख से ज्यादा महिलाओं द्वारा संचालित एमएसई ने 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जिनका मूल्य 99,147 करोड़ रुपये से ज्यादा हैय 42,242 स्टार्टअप्स ने प्लेटफॉर्म के माध्यम से 65,633 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर प्राप्त किए।

आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन में, वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 की अवधि में कीमत और प्रक्रिया की दक्षता से 86,571.69 करोड़ रुपये का मौद्रिक लाभ और कुल सामाजिक बचत 1,76,411.46 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया। 101 वस्तुओं की अन्य ई–मार्केटप्लेस से तुलना में जेम ने 74.3 प्रतिशत वस्तुओं के लिए कम कीमतें दीं, जिससे खर्च में 13.6 प्रतिशत की बचत हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 में भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार खरीद बचत दर्ज की गई थी।

पेटेंट और ट्रेडमार्क एजेंट परीक्षा–2027 के संभावित कार्यक्रम की घोषणा

नई दिल्ली, 08 अगस्त। पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेड मार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय ने ट्रेड मार्क एजेंट परीक्षा (टीएई)–2027 और पेटेंट एजेंट परीक्षा (पीएई)–2027 के संभावित कार्यक्रम की घोषणा की है। ट्रेड मार्क एजेंट परीक्षा संभावित रूप से 9 जनवरी 2027 (शनिवार) को तथा पेटेंट एजेंट परीक्षा 10 जनवरी 2027 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का आयोजन देशभर के 15 केन्द्रों–अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे और तिरुवनंतपुरमकृमें किए जाने का प्रस्ताव है।

पेटेंट एजेंट परीक्षा पेटेंट कानून, 1970 की धारा 126 तथा पेटेंट नियम, 2003 के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती है। ट्रेड मार्क एजेंट परीक्षा ट्रेड मार्क नियम, 2017 के नियम 144 के अनुसार होती है। दोनों परीक्षाओं में तीन चरण शामिल हैं–पेपर–I: 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न–पत्रय पेपर–II: 100 अंकों का विषय पर कध्वर्णनात्मक प्रश्न–पत्र तथा 50 अंकों की मौखिक परीक्षा, जिसका उद्देश्य उम्मीदवार की बौद्धिक संपदा कार्यालय के समक्ष अभ्यास की क्षमता और उपयुक्तता का आकलन करना है।

उम्मीदवारों के लिए पेपर–I और पेपर–II में पृथक–पृथक न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए कुल अंकों का कम–से–कम 60 प्रतिशत एग्रीगेट अंक भी आवश्यक है। निर्धारित सभी पात्रता मानदंड पूरे करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही, यथास्थिति, पेटेंट एजेंट रजिस्टर अथवा ट्रेड मार्क एजेंट रजिस्टर में पंजीकरण के लिए पात्र माने जाएंगे।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और ब्रांडिंग के विस्तार के साथ योग्य पेटेंट एजेंटों और ट्रेड मार्क एजेंटों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। पेटेंट एजेंट आविष्कारकों एवं उद्योगों को पेटेंट आवेदनों का मसौदा, दाखिल करने और अभियोजन में सहायता देते हैंय ट्रेड मार्क एजेंट पंजीकरण, क्लियरेंस सर्च, पोर्टफोलियो प्रबंधन और ब्रांड पहचान के संरक्षण में मदद करते हैं, साथ ही कॉपीराइट तथा भौगोलिक संकेतक (जीआई) के पंजीकरण में भी सहयोग करते हैं। सीजीपीडीटीएम ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से इन परीक्षाओं में भाग लेने का आग्रह किया है, ताकि वे भारत के बौद्धिक संपदा ढांचे को और सशक्त बनाने में योगदान दे सकें।

एससीआई ने 8,000 टीईयू क्षमता वाले 6 बड़े कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए जारी किया 720 मिलियन डॉलर का वैश्विक टेंडर

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। देश की प्रमुख सरकारी नौवहन कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) ने अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक जहाज निर्माण टेंडर जारी किया है। कंपनी ने लगभग 720 मिलियन डॉलर (करीब 6,858 करोड़ रुपये) की लागत से छह आधुनिक कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की है। इस कदम को भारत की समुद्री परिवहन क्षमता बढ़ाने और घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मरीन इनसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, इस टेंडर के तहत 6 सेल्युलर कंटेनर पोत बनाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 8,000 ट्वेंटी–फुट इक्विवेलेंट यूनिट (टीईयू) होगी। टीईयू कंटेनर जहाजों की माल ढुलाई क्षमता मापने की एक मानक इकाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, छह जहाजों में से दो जहाजों का ऑर्डर पक्का होगा, जबकि शेष चार जहाज वैकल्पिक श्रेणी में रखे गए हैं। इससे एससीआई को भविष्य की जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त जहाजों का ऑर्डर देने की सुविधा मिलेगी।

टेंडर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारतीय शिपयार्ड्स को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल (आरओएफआर) व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत यदि किसी विदेशी शिपयार्ड की बोली सबसे कम रहती है, तो योग्य भारतीय शिपयार्ड को उस कीमत का मिलान करने का अवसर दिया जाएगा।

यदि पहला पात्र भारतीय शिपयार्ड विदेशी कंपनी की बोली से मेल नहीं खा पाता, तो यह अवसर अगले योग्य भारतीय शिपयार्ड को दिया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाना है।

एससीआई ने उन भारतीय शिपयार्ड्स के लिए भी रास्ता खोला है, जिनके पास बड़े कंटेनर जहाज बनाने का पूर्व अनुभव नहीं है। ऐसे शिपयार्ड अनुभवी विदेशी जहाज निर्माताओं के साथ तकनीकी साझेदारी कर इस टेंडर में भाग ले सकते हैं।

टेंडर की शर्तों के अनुसार, विदेशी तकनीकी साझेदार ने पिछले 10 वर्षों में कम से कम दो कंटेनर जहाज (5,000 टीईयू या उससे अधिक क्षमता वाले) सफलतापूर्वक बनाए और डिलीवर किए हों। साथ ही वे जहाज वर्तमान में संचालन में होने चाहिए। विदेशी साझेदार को निर्माण प्रक्रिया के दौरान बुनियादी और विस्तृत डिजाइन सहायता भी प्रदान करनी होगी।–आईएएनएस

विश्व आदिवासी दिवसः धरती, जंगल और परंपराओं के रखवाले, जानें 'प्रकृति के प्रहरियों' की कहानी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। आदिवासी समाज सदियों से प्रकृति के बेहद करीब रहकर अपनी जिंदगी जीता आया है। जंगल, पहाड़, नदियां और जमीन उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति का हिस्सा हैं। विश्व आदिवासी दिवस भी इसी बात पर जोर देता है कि दुनिया की विविधता सिर्फ बड़े शहरों और आधुनिक जीवनशैली से नहीं बनती। जंगलों, पहाड़ों और गांवों में सदियों से अपनी संस्कृति को संजोकर रखने वाले समुदाय भी इस विविधता का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक दिन आदिवासी समुदायों की चर्चा करना नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों और समस्याओं को समझना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में हर साल 9 अगस्त को विश्व के मूल निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संबंधी कार्य समूह की आदिवासी आबादी पर पहली बैठक हुई थी।

भारत में आदिवासी समुदायों की अपनी अलग–अलग भाषाएं, बोलियां, पहनावे, खान–पान, लोकगीत, नृत्य और धार्मिक परंपराएं हैं। देश के अलग–अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। उनके त्योहारों और पारंपरिक आयोजनों में प्रकृति का खास महत्व दिखाई देता है।

आदिवासी समाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी परंपराएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित हैं। लोकगीतों और लोककथाओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास और अनुभव आगे बढ़ते रहे हैं। पारंपरिक नृत्य और संगीत आज भी उनकी सामुदायिक एकता की मजबूत पहचान हैं।

आदिवासी समुदायों का जंगलों से रिश्ता बेहद पुराना है। जंगल उन्हें भोजन, औषधियां, लकड़ी और रोजमर्रा की कई जरूरतों की चीजें देते हैं। लेकिन इसके बदले प्रकृति की रक्षा करना भी उनकी जीवनशैली का हिस्सा रहा है। पेड़–पौधों, नदियों और वन्यजीवों को लेकर उनके पारंपरिक ज्ञान की अक्सर चर्चा होती है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली से भी कई महत्वपूर्ण बातें सीखने की जरूरत महसूस होती है। सीमित संसाधनों में संतुलित जीवन जीना और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है।

आदिवासी समुदायों की पहचान का एक बड़ा हिस्सा उनकी भाषाओं में छिपा है। कई आदिवासी भाषाएं और बोलियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन बदलते समय, शिक्षा और रोजगार के नए तरीकों तथा मुख्यधारा की भाषाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण कई छोटी भाषाओं के सामने अस्तित्व का संकट भी है। भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसमें किसी समाज का इतिहास, ज्ञान और संस्कृति भी जुड़ी होती है। इसी कारण आदिवासी भाषाओं को बचाना उनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाने जैसा है। समय के साथ सरकारों और विभिन्न संगठनों की ओर से आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं और प्रयास किए गए हैं।–आईएएनएस

जीआई–टैग वाले मखाना की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई

नई दिल्ली, 08 अगस्त (हि.स.)। बिहार के जीआई–टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार के दरभंगा से पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई–टैग प्राप्त मिथिला मखाना की खेप समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इसे भारतीय कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बिहार के बिहटा (बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया) से ऑस्ट्रेलिया के लिए जीआई–टैग वाले 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना के पहले कमर्शियल समुद्री शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया है। मंत्रालय ने कहा कि दरभंगा जिले के मखाना उत्पादकों से लिए गए इस कंसाइनमेंट से बिहार के खास जीआई प्रोडक्ट की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत होने और एक्सपोर्ट के जरिए किसानों के लिए कमाई के बेहतर मौके बनने की उम्मीद है।